भारत का संघ

बनाम

मेसर्स एम्बीका निर्माण

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या: 11114/2009)

16 मार्च, 2016

[रंजन गोगोई, अरुण मिश्रा और प्रफुल्ल सी. पंत, जे. जे.]

मध्यस्थता अधिनियम, 1940: धारा 3, 31 — यदि अनुबंध रोकता है तो मुकदमेबाजी का इंतजार ब्याज देने की मध्यस्थ की शक्ति- अभिनिर्धारित: यदि अनुबंध स्पष्ट रूप से ब्याज लटकन के अवार्ड पर रोक लगाता है, तो इसे मध्यस्थ द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता है-विलंबित भुगतान मुकदमेबाजी का इंतजार देने के लिए बार को मध्यस्थ द्वारा ब्याज लटकन देने के लिए एक्सप्रेस बार के रूप में आसानी से अनुमान नहीं लगाया जाएगा क्योंकि मध्यस्थ की शक्ति को हटाने पर विभिन्न प्रासंगिक पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए-लटकन वाले ब्याज का अवार्ड अन्य बातों के साथ साथ साथ समझौते के समग्र इरादे पर निर्भर करना चाहिए और जिसे स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है।

संदर्भ का जवाब देते हुए, न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया-

1. 1940 के अधिनियम की खंड 3 उन प्रावधानों से संबंधित है जो मध्यस्थता समझौते में निहित हैं। खंड 3 के प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि जब तक मध्यस्थता समझौते में कोई अलग इरादा व्यक्त नहीं किया जाता है, तब तक समझौते में पहली अनुसूची में निहित प्रावधान शामिल होंगे जहां तक वे संदर्भ पर लागू होते हैं। पहली अनुसूची के प्रावधानों में 8 अनुच्छेद हैं। यह प्रदान करता है। एकमात्र मध्यस्थ के संदर्भ

में और यदि मध्यस्थों की संख्या समान है, तो अंपायर की नियुक्ति भी प्रदान की जाती है। एक मध्यस्थ को संदर्भ पर प्रवेश करने की तारीख से 4 महीने के भीतर अवार्ड पारित करना आवश्यक है। यदि मध्यस्थ निर्दिष्ट समय के भीतर अवार्ड पारित करने में विफल रहता है तो अंपायर 2 महीने के भीतर अवार्ड देगा। पहली अनुसूची के पैरा 6 में प्रावधान है कि मध्यस्थ या अंपायर अलग-अलग मामलों की जांच करेगा और अवार्ड अंतिम और बाध्यकारी होगा। मध्यस्थ या अंपायर के पास गवाहों की जांच करने और प्रासंगिक दस्तावेजों को पेश करने की शक्ति है। अनुसूची । के पैरा 8 में संदर्भ लागत का प्रावधान है और अवार्ड मध्यस्थ के विवेकाधिकार में होंगे। [पैरा 5] [816-ए-डी]

2. "न्यायालय" को अधिनियम की खंड 2 (सी) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है एक सिविल न्यायालय जिसे संदर्भ के विषय-वस्तु को बनाने वाले प्रश्नों का निर्णय करने का अधिकार क्षेत्र है। न्यायालय अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट शक्ति का प्रयोग कर सकता है। हालाँकि, मध्यस्थ एक अदालत नहीं है। मध्यस्थ समझौते का परिणाम है। वह पक्षों के बीच हुए समझौते के अनुसार विवादों का फैसला करता है। मध्यस्थता विवादों के समाधान के लिए एक वैकल्पिक मंच है लेकिन एक मध्यस्थ वास्तव में अदालतों को प्रदान की गई सभी शक्तियों का आनंद नहीं लेता है या उसके पास नहीं है। अधिनियम की खंड 29 अदालत को डिक्री की तारीख से ब्याज देने की शक्ति प्रदान करती है। सी. पी. सी. की खंड 34 अदालत को मुकदमा की स्थापना से पहले और मुकदमा विचाराधीनता होने और डिक्री के बाद ब्याज देने की शक्ति प्रदान करती है। 1996 के अधिनियम की खंड 31(7)(ए) मध्यस्थ को "जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो", मुकदमेबाजी का इंतजार का अधिकार प्रदान करती है। इस प्रकार, खंड 31(7)(ए) में निहित प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि पक्षों के बीच अनुबंध को महत्व दिया गया है और यह मध्यस्थ के लिए बाध्यकारी है। मध्यस्थ की शक्ति का निर्णय करते समय मध्यस्थता खंड पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है और यदि

ब्याज देने पर अनुबंध में कोई प्रतिबंध निहित है, तो यह किन मदों पर काम करता है और मध्यस्थता खंड में मध्यस्थ को क्या शक्तियां प्रदान की गई हैं और क्या ब्याज देने पर प्रतिबंध निश्चित अवधि तक सीमित किया गया है या यह मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही विचाराधीनता रहने से संबंधित है। मुकदमेबाजी का इंतजार ब्याज का अनुदान कई कारकों पर निर्भर कर सकता है जैसे कि समझौते में उपयोग की गई वाक्यांश-रचना, मध्यस्थता से संबंधित शक्ति प्रदान करने वाले खंड, मध्यस्थ को संदर्भित दावे और विवाद की प्रकृति और ब्याज देने की किस वस्तु की शक्ति को छीन लिया गया है और किस अवधि के लिए। [पैरा 6,7,16,23] [816-ई; 817-ए-सी; 828-डी-ई; 836-सी-डी]

पोर्ट ऑफ कलकत्ता के लिए न्यासी मंडल बनाम इंजीनियर्स डी-स्पेस-एज 1995(6) पूरक एससीआर 327:(1996) 1 एस.सी.सी. 516; मदनानी निर्माण निगम (पी) लिमिटेड बनाम.भारत संघ और अन्य 2009(16) एस.सी.आर. 216:(2010) 1 एससीसी 549; सचिव, सिंचाई विभाग, उड़ीसा सरकार अन्य अन्य बनाम जी. सी. रॉय 1991 (3) पूरक एस.सी.आर. 417:(1992) 1 एससीसी 508; निष्पादन अभियंता, ढेंकनाल लघु सिंचाई प्रभाग, उड़ीसा और अन्य बनाम एन. सी. बुधराज (डी) विधिक प्रतिनिधि. और अन्य द्वारा, 2001 (1) एससीआर 264:(2001) 2 SCC 721; सईद अहमद एंड कंपनी बनाम "उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2009 (10) एससीआर 841: (2009) 12 एस.सी.सी. 26; श्री कामची अम्मान कंस्ट्रक्शंस बनाम डिवीजनल रेलवे मैनेजर (वर्क्स), पालघाट और अन्य 2010 (10) एससीआर 487:(2010) 8 एससीसी 767; रायपुर विकास प्राधिकरण और अन्य बनाम मेसर्स. चोखामल ठेकेदार और अन्य 1989 (3) एससीआर 144:(1989) 2 एस. सी. सी. 721; कार्यकारी अभियंता (सिंचाई) बालीमेला और अन्य बनाम अभादुता जेना और अन्य 1988 (1) एससीआर 253: (1988) 1 एस.सी.सी. 418; नचियप्पा चेट्टियार और अन्य बनाम सुब्रमण्यम चेट्टियार

ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 307:1960 एस.सी.आर. 209; सतिंदर सिंह बनाम अमराव सिंह और अन्य। ए.आई.आर 1961 एस.सी 908:1961 एससीआर 676; फर्म मदन/अल रोशनलाल महाजन बनाम हुकुमचंद मिल्स लिमिटेड, इंदौर, एआईआर 1967 एससी 1030:1967 एस.सी.आर. 105; यूनियन ऑफ इंडिया बनाम "बंगो स्टील फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड। ए.आई.आर 1967 एस.सी. 1032:1967 एस.सी.आर. 324; अशोक कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम भारत संघ (1971) 3 एस.सी.सी. 66; मध्य प्रदेश राज्य बनाम मेसर्स सेठ एंड स्केल्टन प्राइवेट लिमिटेड 1972 (3) एस. सी. आर. 233:(1972) 1 एस.सी.सी. 702; हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य 1992 (1) पूरक एससीआर 297:(1992) 4 एससीसी 217; उड़ीसा राज्य बनाम बी. एन. अग्रवाल, 1997 (1) एस.सी.आर. 704:(1997) 2 एससीसी 469; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरीश चंद्र एंड कंपनी 1998 (2) पूरक एससीआर 660:(1999) 1 एसएससी 63; अधीक्षण अभियंता बनाम बी. सुब्बा रेड्डी 1999 (2) एस.सी.आर. 880:(1999) 4 एससीसी 423; राजस्थान राज्य और अन्य बनाम फेरो कंक्रीट कंस्ट्रक्शन (प्राइवेट) लिमिटेड 2009 (10) एससीआर 31:(2009) 12 एस.सी.सी. 1; भारत संघ बनाम ब्राइट पावर प्रोजेक्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड 2015 (6) एससीआर 488:(2015) 9 एस.सी.सी. 695; भारत संघ बनाम क्राफ्टर्स इंजीनियरिंग एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड 2011(8) एससीआ 196:(2011) 7 एस.सी.सी. 279; टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड 2012(8) एस.सी.आर. 813:(2012) 12 एस.सी.सी. 10-संदर्भित।

<u>मामला कानून संदर्भ</u>

1995 (6) पूरक एस.सी.आर. 327	संदर्भित	पैरा 1
2009 (16) एस.सी.आर. 216	संदर्भित	पैरा 1

1991 (3) पूरक एस.सी.आर. 417	संदर्भित	पैरा 1
2001 (1) एस.सी.आर. 264	संदर्भित	पैरा 1
2009 (10) एस.सी.आर. 841	संदर्भित	पैरा 1
2010 (10) एस.सी.आर. 487	संदर्भित	पैरा 1
1989 (3) एस.सी.आर. 144	संदर्भित	पैरा 8
1988 (1) एस.सी.आर. 253	संदर्भित	पैरा 8
1960 एस.सी.आर. 209	संदर्भित	पैरा 8
1961 एस.सी.आर. 676	संदर्भित	पैरा 8
1967 एस.सी.आर. 105	संदर्भित	पैरा 8
1967 एस.सी.आर. 324	संदर्भित	पैरा 8
(1971) 3 एस.सी.सी. 66	संदर्भित	पैरा 8
1972 (3) एस.सी.आर. 233	संदर्भित	पैरा 8
1992 (1) पूरक एस.सी.आर. 297	संदर्भित	पैरा 10
1997 (1) एस.सी.आर. 704	संदर्भित	पैरा 11
1998 (2) पूरक एस.सी.आर. 660	संदर्भित	पैरा 13
1999 (2) एस.सी.आर. 880	संदर्भित	पैरा 15
2009 (10) एस.सी.आर. 31	संदर्भित	पैरा 15
2015 (6) एस.सी.आर. 488	संदर्भित	पैरा 16
2111 (8) एस.सी.आर. 196	संदर्भित	पैरा 18

2012 (8) एस.सी.आर. 813 संदर्भित पैरा 22

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः विशेष अनुमति अपील (सिविल) सं. 11114/2009

ए.पी.ओ. सं. 5/2008 में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.03.2008 को पारित निर्णय और आदेश से।

के साथ

एस.एल.पी. (सी) संख्या 17219/2009

ए. के. पांडा, वरिष्ठ अधिवक्ता, अजय सिंह,रंजीत कुमार, एस.एन. तेरडाल (सुश्री सुषमा सूरी के लिए) अधिवक्ता अपीलकर्ता के लिए उसके साथ।

राज कुमार मेहता, अभिषेक उपाध्याय, सुश्री हिमांशी एंडली, अधिवक्ता उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश अरुण मिश्रा. जे. द्वारा सुनाया गया:-

1. संदर्भ में शामिल मुद्दा मध्यस्थ की मुकदमेबाजी का इंतजार देने की शक्ति के संबंध में है जब अनुबंध में मध्यस्थता अधिनियम, 1940 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत आने वाले मामले में ब्याज देने के लिए बार शामिल है। इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने पोर्ट ऑफ कलकत्ता बनाम इंजीनियर्स-डी-स्पेस-एज (1996) 1 एस.सी.सी. 516; और मदनानी कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य न्यासी मंडल के फैसलों की शुद्धता पर संदेह किया था। भारत संघ और अन्य (2010) 1 एस. सी. सी. 549. सचिव, सिंचाई विभाग, उड़ीसा सरकार अन्य अन्य में संविधान पीठ के फैसले के फैसले को ध्यान में रखते हुए। जी. सी. रॉय (1992) 1 एस. सी. सी. 508 और कार्यकारी अभियंता, ढेंकनाल लघु सिंचाई प्रभाग, उड़ीसा और अन्य अन्यएल. आर. अन्य अन्य द्वारा एन. सी. बुधराज (डी)। (2001) 2 एस. सी. सी. 721 जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मध्यस्थ के

पास पूर्व-संदर्भ अवधि, विचाराधीन अवधि अन्य भविष्य की अवधि के लिए ब्याज देने का अधिकार क्षेत्र अन्य अधिकार था यदि ब्याज देने के संबंध में अनुबंध में कोई मुकदमेबाजी का इंतजार नहीं थी। सईद अहमद एंड कंपनी बनाम में इंजीनियर्स-डी-स्पेस एज (उपरोक्त) में निर्णय की शुद्धता के बारे में संदेह व्यक्त किया गया था। यू. पी. और अन्य का राज्य। (2009) 12 एस. सी. सी. 26 और श्री कामची अम्मान कंस्ट्रक्शंस अन्य डिवीजनल रेलवे मैनेजर (वर्क्स), पालघाट और अन्य। (2010) 8 एससीसी 767। इसलिए मामले को निर्णय के लिए एक बड़ी पीठ को भेजा गया था।

2. इस मामले का एक उतार-चढ़ाव वाला इतिहास है। सी. एस. टी.-9 स्लीपर्स में एम. एस. फ्लैटों से टाई बार बनाने के लिए मेसर्स अम्बिका कंस्ट्रक्शन की निविदा 8.9.1989 पर स्वीकार की गई थी। अंतिम समझौता 30.11.1989 पर निष्पादित किया गया था। काम 21.11.1990 पर पूरा किया गया था। भुगतान के संबंध में, पक्षों के बीच कुछ मतभेद और विवाद उत्पन्न हुए। इस प्रकार मेसर्स अंबिका कंस्ट्रक्शन ने एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया। चूंकि याचिकाकर्ता मेसर्स अंबिका कंस्ट्रक्शन गंभीर वित्तीय कठिनाइयों में था, इसलिए इसने पूर्ण और अंतिम निपटान में राशि स्वीकार कर ली। बाद में, भारत संघ ने याचिकाकर्ता को 11.3.1991 पर सूचित किया कि मामला विचाराधीन है। हालांकि मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं की गई थी। अधिनियम की खंड 20 के तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष मामले को मध्यस्थता के लिए भेजने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। 2.6.1992 पर उच्च न्यायालय ने न्यायालय में मध्यस्थता समझौता दायर करने का निर्देश दिया और मध्यस्थता खंड के संदर्भ में दो मध्यस्थों को नियुक्त किया। उक्त मध्यस्थ अवार्ड को प्रकाशित करने में विफल रहे और इस तरह संयुक्त मध्यस्थों के अधिकार को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया और एक अन्य एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया। एकमात्र मध्यस्थ ने अंततः 30.12.1997 पर अवार्ड प्रकाशित किया। भारत संघ

द्वारा दायर एक आवेदन पर, उच्च न्यायालय ने 9.4.1998 दिनांकित आदेश के माध्यम से मध्यस्थ को वस्तु-वार विवरण देने के लिए अवार्ड भेजा। 12.5.1998 पर एकमात्र मध्यस्थ ने वस्तु-वार अवार्ड प्रकाशित किया। एक बार फिर भारत संघ ने उच्च न्यायालय के समक्ष इस पर सवाल उठाया। अवार्ड को इस आधार पर अलग रखा गया था कि मध्यस्थ ने समझौते के खंड 64(3)(ए)(iii) के संदर्भ में एक बोधगम्य अवार्ड नहीं दिया था और दिनांक 5.3.1991 के पूरक समझौते को प्रभावी नहीं किया था। याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा 15.10.2004 पर खारिज कर दिया गया था, जिसके खिलाफ एक एसएलपी दायर की गई थी जिसमें अनुमति दी गई थी और अंततः सीए No.6621/2005 को अनुमति दी गई थी और इस न्यायालय द्वारा मध्यस्थ को कारण बताने और नया अवार्ड पारित करने के लिए पारित किए गए 7.11.2005 के आदेश के माध्यम से मामला प्रेषित किया गया था। इसके बाद, मध्यस्थ ने 11.2.2006 पर एक नया अवार्ड पारित किया। भारत संघ द्वारा अधिनियम की धारा 30 और 33 के तहत फिर से एक आवेदन दायर किया गया था। एकल न्यायाधीश ने 26.6.2007 दिनांकित आदेश के माध्यम से आवेदन को खारिज कर दिया। भारत संघ ने वापस बुलाने के लिए एक आवेदन दायर किया। 26.6.2007 दिनांकित आदेश को वापस ले लिया गया। एकल न्यायाधीश ने दिनांक '22.8.2007' के आदेश के माध्यम से पूर्व-संदर्भ अवधि के लिए ब्याज के संबंध में निर्णय को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि रुपये 9,82,660/- की मूल राशि पर ब्याज की अनुमति दी जाएगी-'1.9.1992' से 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से, जिस तारीख से मूल मध्यस्थ ने संदर्भ दर्ज किया था। खण्ड पीठ के समक्ष एक अपील दायर की गई थी और दावे स..6 और 7 के संबंध में इसे आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी। इससे आहत मेसर्स अंबिका कंस्ट्रक्शन ने एस.एल.पी.[सी] स. 17219/2009 को प्राथमिकता दी थी। इस

न्यायालय और भारत संघ ने एस.एल.पी.[सी] सं. 11114/2009 में उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश पर भी हमला किया है।

3. विचार के लिए एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या एक मध्यस्थ के पास अधिनियम के दायरे में आने वाले मामले में मुकदमेबाजी का इंतजार ब्याज देने की शक्ति है और इंजीनियर्स डी-स्पेस एज (उपरोक्त) और मदनानी कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड (उपर्युक्त) में इस न्यायालय के निर्णयों का सही निर्णय लिया गया है।

4. भारत संघ की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि मध्यस्थ अनुबंध की शर्तों से बाध्य है और अनुबंध के प्रतिबंध के मामले में ब्याज नहीं दे सकता है। दूसरी ओर, मैसर्स अंबिका कंस्ट्रक्शन की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि मदनानी कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (प्रा.) लिमिटेड (सुप्रा) में इंजीनियर्स-डी-स्पेस एज (सुप्रा) के निर्णय को देखते हुए ब्याज के अवार्ड पर प्रतिबंध लगाने वाले अनुबंध समझौते की शर्तों के बावजूद पूर्व-संदर्भ अवधि को शामिल किया जाएगा, न कि मुकदमेबाजी का इंतजार को।

5. कुछ प्रावधान हैं जो मध्यस्थता समझौते में वैधानिक रूप से निहित हैं जब तक कि समझौते में शामिल नहीं किए जाते हैं। 1940 के अधिनियम की खंड 3 उन प्रावधानों से संबंधित है जो मध्यस्थता समझौते में निहित हैं। खंड 3 नीचे दी गई हैः

> "3. मध्यस्थता समझौते में निहित प्रावधान। —एक मध्यस्थता समझौता, जब तक कि उसमें कोई अलग इरादा व्यक्त नहीं किया जाता है, यह माना जाएगा कि इसमें पहली अनुसूची में निर्धारित प्रावधान शामिल हैं जहां तक वे संदर्भ पर लागू होते हैं।"

खंड 3 के प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि जब तक मध्यस्थता समझौते में कोई अलग इरादा व्यक्त नहीं किया जाता है, तब तक समझौते में पहली अनुसूची में निहित प्रावधान शामिल होंगे जहां तक वे संदर्भ पर लागू होते हैं। पहली अनुसूची के प्रावधानों में 8 अनुच्छेद हैं। यह एकमात्र मध्यस्थ के लिए संदर्भ प्रदान करता है और यदि मध्यस्थों की संख्या समान है, तो अंपायर की नियुक्ति भी प्रदान की जाती है। एक मध्यस्थ को संदर्भ में प्रवेश करने की तारीख से 4 महीने के भीतर अवार्ड पारित करना आवश्यक है। यदि मध्यस्थ निर्दिष्ट समय के भीतर अवार्ड पारित करने में विफल रहता है तो अंपायर 2 महीने के भीतर अवार्ड देगा। पहली अनुसूची के पैरा 6 में प्रावधान है कि मध्यस्थ या अंपायर अलग-अलग मामलों की जांच करेगा और अवार्ड अंतिम और बाध्यकारी होगा। मध्यस्थ या अंपायर के पास गवाहों की जांच करने और प्रासंगिक दस्तावेजों को पेश करने की शक्ति है। अनुसूची के पैरा 8 में संदर्भ लागत का प्रावधान है और अवार्ड मध्यस्थ के विवेकाधिकार में होंगे।

6. ""न्यायालय" को अधिनियम की खंड 2 (सी) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है एक दीवानी न्यायालय जिसे संदर्भ के विषय-वस्तु को बनाने वाले प्रश्नों का निर्णय करने का अधिकार क्षेत्र है। अधिनियम की खंड 41 यहाँ नीचे निकाली गई हैः

> "41. न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियाँ-– इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अधीनः
>
> (अ) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के प्रावधान, न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाहियों और इस अधिनियम के तहत सभी अपीलों पर लागू होंगे, और

(ब) न्यायालय को, मध्यस्थता कार्यवाहियों के उद्देश्य से और उनके संबंध में, दूसरी अनुसूची में निर्धारित किसी भी मामले के संबंध में आदेश देने की वही शक्ति होगी जो उसके उद्देश्य के लिए और न्यायालय के समक्ष किसी भी कार्यवाही के संबंध में हैः

बशर्ते कि सी.आई.(बी) की किसी भी बात को किसी ऐसी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए नहीं लिया जाएगा जो ऐसे मामलों में से किसी के संबंध में आदेश देने के लिए मध्यस्थ या अंपायर में निहित हो। "

न्यायालय अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट शक्ति का प्रयोग कर सकता है। हालाँकि, मध्यस्थ एक अदालत नहीं है। मध्यस्थ समझौते का परिणाम है। वह पक्षों के बीच हुए समझौते के अनुसार विवादों का फैसला करता है। मध्यस्थता विवादों के समाधान के लिए एक वैकल्पिक मंच है, लेकिन एक मध्यस्थ वास्तव में अदालतों को प्रदत्त सभी शक्तियों का आनंद नहीं लेता है या उसके पास नहीं होता है।

7. अधिनियम की खंड 29 अदालत को डिक्री की तारीख से ब्याज देने की शक्ति प्रदान करती है। सी.पी.सी. की खंड 34 अदालत को मुकदमा की स्थापना से पहले और मुकदमा विचाराधीनता होने और डिक्री के बाद ब्याज देने की शक्ति प्रदान करती है।

8. जी.सी. रॉय (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने मुकदमेबाजी का इंतजार ब्याज देने की मध्यस्थ की शक्ति के सवाल पर विचार किया है और यह निर्धारित किया गया है कि यदि मध्यस्थता समझौता या अनुबंध स्वयं ब्याज प्रदान करता है, तो मध्यस्थ के पास ब्याज देने का अधिकार क्षेत्र होगा। इसी तरह,

जहां समझौते में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि देय राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा, मध्यस्थ के पास मुकदमेबाजी का इंतजार देने की कोई शक्ति नहीं है। जी. सी. रॉय (सुप्रा) में इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया हैः

> "XXX यदि मध्यस्थता समझौता या अनुबंध स्वयं एक पक्ष से दूसरे पक्ष को देय राशि पर ब्याज देने का प्रावधान करता है, तो ब्याज देने के लिए मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र की अनुपस्थिति में के बारे में कोई सवाल नहीं उठ सकता है क्योंकि उस मामले में मध्यस्थ के पास लंबित ब्याज भी देने की शक्ति है। इसी तरह, जहां समझौते में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि देय राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा, मध्यस्थ के पास मुकदमेबाजी का इंतजार देने की कोई शक्ति नहीं है। लेकिन जहां समझौते में देय राशि पर ब्याज देने या देने से इनकार करने का प्रावधान नहीं है, तो सवाल उठता है कि क्या ऐसी स्थिति में मध्यस्थ के पास मुकदमेबाजी का इंतजार देने की शक्ति और अधिकार है। " जी. सी. रॉय (उपरोक्त) में शामिल प्रश्न मध्यस्थ के संदर्भ में प्रवेश करने की तारीख से लेकर अवार्ड देने की तारीख तक की अवधि के लिए ब्याज के अवार्ड के संबंध में था। जी. सी. रॉय (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने रायपुर विकास प्राधिकरण और अन्य बनाम मेसर्स चोखामल ठेकेदार और अन्य, (1989) 2 एससीसी 721; कार्यकारी अभियंता (सिंचाई) बालीमेला और अन्य बनाम अभादुता जेना और अन्य, (1988) 1 एस. सी. सी. 418; नचियप्पा चेट्टियार और अन्य, बनाम सुब्रमण्यम चेट्टियार, ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 307; सतिंदर सिंह बनाम अमराव सिंह और अन्य, ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 908; फर्म मदनलाल रोशनलाल

महाजन बनाम हुकुमचंद मिल्स लिमिटेड, इंदौर, ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1030; भारत संघ बनाम बंगो स्टील फर्नीचर प्रा. लिमिटेड, ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1032; अशोक कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम भारत संघ, (1971) 3 एस. सी. सी. 66; एम. पी. राज्य बनाम मेसर्स सेठ एंड स्केल्टन प्राइवेट लिमिटेड, (1972) 1 एस. सी. सी. 702, विभिन्न विदेशी न्यायालयों के निर्णय और उच्च न्यायालय के निर्णय। इस न्यायालय ने पैरास 36 और 37 में हैल्सबरी के इंग्लैंड के कानूनों का भी उल्लेख किया हैः-

"36. 534. अभिव्यक्त और निहित खंड— सामान्य तौर पर, मध्यस्थता समझौते के पक्षकार इसमें ऐसे खंड शामिल कर सकते हैं जो वे उचित समझते हैं। अधिनियम द्वारा, हालांकि, एक मध्यस्थता समझौते में कुछ शर्तें निहित हैं जब तक कि उसमें एक विपरीत इरादा व्यक्त या निहित न हो। इसके अलावा, यह आम तौर पर एक मध्यस्थता समझौते का एक निहित शब्द है कि मध्यस्थ को सामान्य कानून के अनुसार विवाद का फैसला करना चाहिए। इसमें प्रक्रिया के रूप में बुनियादी नियम शामिल हैं, हालांकि पक्ष उन नियमों से अलग होने के लिए स्पष्ट रूप से या निहित रूप से सहमति दे सकते हैं। सामान्य सिद्धांत जिन पर एक समझौते में शर्तें निहित हैं, उन पर इस संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए कि समझौता एक मध्यस्थता से संबंधित है"

37. पृष्ठ 303 पर, पैरा 580 (चौथा संस्करण। , खण्ड. 2) ब्याज के अवार्ड से संबंधित, यह पढ़ता हैः

"580. रुचि है। — एक मध्यस्थ या अंपायर के पास वाद हेतुक उत्पन्न होने की तारीख और अवार्ड की तारीख के बीच की अवधि के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए किसी भी ऋण या नुकसान की राशि पर ब्याज देने की शक्ति होती है। "

अंततः, जी. सी. रॉय (सुप्रा) मामले में, इस न्यायालय ने इस सवाल का जवाब दिया है कि क्या मध्यस्थ के पास ब्याज लटकाने का अधिकार है। उनके अधिपतियों ने दोहराया है कि उन्होंने उस स्थिति से निपटा है जहां समझौते में इस तरह के ब्याज के अनुदान का प्रावधान नहीं है और न ही यह इस तरह के अनुदान को प्रतिबंधित करता है जब समझौता ब्याज के अवार्ड के बारे में चुप है। इस न्यायालय ने रिपोर्ट के पैरा 43 में विभिन्न सिद्धांतों को इस प्रकार निर्धारित किया हैः

43. सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या मध्यस्थ के पास मुकदमेबाजी का इंतजार का अधिकार है, और यदि है तो किस सिद्धांत पर। हमें दोहराना चाहिए कि हम ऐसी स्थिति से निपट रहे हैं जहां समझौता इस तरह के ब्याज के अनुदान के लिए प्रावधान नहीं करता है और न ही यह इस तरह के अनुदान को प्रतिबंधित करता है। दूसरे शब्दों में, हम एक ऐसे मामले से निपट रहे हैं जहां समझौता ब्याज देने के बारे में चुप है। उपरोक्त निर्णयों के संदर्भ में, निम्नलिखित सिद्धांत सामने आते हैंः

(i) धन के उपयोग से वंचित व्यक्ति जिसे वह वैध रूप से हकदार है, उसे अभाव के लिए क्षतिपूर्ति का अधिकार है, इसे किसी भी नाम से

कहें। इसे ब्याज, क्षतिपूर्ति या नुकसान कहा जा सकता है। यह मूल विचार मध्यस्थ के समक्ष विवाद के लंबित रहने की अवधि के लिए उतना ही वैध है जितना कि मध्यस्थ के संदर्भ में प्रवेश करने से पहले की अवधि के लिए है। यह सिविल प्रक्रिया संहिता की खंड 34 का सिद्धांत है और मध्यस्थ के मामले में अन्यथा मानने का कोई कारण या सिद्धांत नहीं है।

(ii) पक्षकारों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थ एक वैकल्पिक रूप (एस. आई. सी. मंच) है। यदि ऐसा है, तो उसके पास पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी विवादों या मतभेदों को तय करने की शक्ति होनी चाहिए। यदि मध्यस्थ के पास मुकदमेबाजी का इंतजार देने की कोई शक्ति नहीं है, तो यह दावा करने वाले पक्ष को उस उद्देश्य के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा, भले ही उसने मध्यस्थ से अन्य दावों के संबंध में संतुष्टि प्राप्त की हो। इससे कार्यवाही कई गुना बढ़ जाएगी।

(iii) मध्यस्थ एक समझौते का निर्माता होता है। पक्षकारों के लिए यह खुला है कि वे उन्हें ऐसी शक्तियां प्रदान करें और उनके लिए ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करें, जिसका वे पालन करें, जब तक कि वे कानून के खिलाफ नहीं हैं। (मध्यस्थता अधिनियम की खंड 41 और खंड 3 का प्रावधान इस बिंदु को स्पष्ट करता है)। फिर भी, समझौता कानून के अनुरूप होना चाहिए। मध्यस्थ को देश के सामान्य कानून और समझौते के अनुसार भी कार्य करना चाहिए और अपना निर्णय देना चाहिए।

(iv) वर्षों से, अंग्रेजी और भारतीय अदालतों ने इस धारणा पर कार्रवाई की है कि जहां समझौता निषेध नहीं करता है और संदर्भ का एक पक्ष ब्याज के लिए दावा करता है, मध्यस्थ के पास मुकदमेबाजी का इंतजार का अधिकार होना चाहिए। सेठ थावरदास फेरुमल बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 468 का इस न्यायालय के बाद के फैसलों में पालन नहीं किया गया है। यह इस आधार पर समझाया और अलग किया गया है कि उस मामले में ब्याज का कोई दावा नहीं था, बल्कि केवल बिना किसी नुकसान के लिए दावा था। यह बार-बार कहा गया है कि उक्त निर्णय में टिप्पणियों का उद्देश्य किसी भी ऐसे आत्यन्तिक या सार्वभौमिक नियम को निर्धारित करना नहीं था जैसा कि वे पहली नज़र में प्रतीत होते हैं। जब तक कार्यकारी अभियंता (सिंचाई) बालीमेला अन्य अन्य। अभादुता जेना और अन्य, (1988) 1 एस. सी. सी. 418 देश के लगभग सभी न्यायालयों ने मध्यस्थ की मुकदमेबाजी का इंतजार राशि देने की शक्ति को बरकरार रखा था। निरंतरता और निश्चितता कानून की एक अत्यधिक वांछनीय विशेषता है।

(v) मुकदमेबाजी का इंतजार मूल कानून का विषय नहीं है, जैसे कि संदर्भ (पूर्व-संदर्भ अवधि) से पहले की अवधि के लिए ब्याज। पक्षों के बीच पूर्ण न्यायाधीश करने के लिए, ऐसी शक्ति का हमेशा अनुमान लगाया गया है। ”

“44. उपरोक्त विचार को ध्यान में रखते हुए, हम सोचते हैं कि निम्नलिखित सही सिद्धांत है जिसका इस संबंध में पालन किया जाना चाहिएः

जहां पक्षों के बीच समझौता ब्याज देने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है और जहां कोई पक्ष ब्याज का दावा करता है और वह विवाद (मूल राशि के दावे के साथ या स्वतंत्र रूप से) मध्यस्थ को भेजा जाता है, तो उसके पास मुकदमेबाजी का इंतजार देने की शक्ति होगी। यह इस कारण से है कि ऐसे मामले में यह माना जाना चाहिए कि ब्याज पक्षों के बीच समझौते का एक निहित शब्द था और इसलिए जब पक्ष अपने सभी विवादों को मध्यस्थ के पास भेजते हैं या विवाद को ब्याज के रूप में संदर्भित करते हैं, तो उसके पास ब्याज देने की शक्ति होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि हर मामले में मध्यस्थ को अनिवार्य मुकदमेबाजी का इंतजार का भुगतान करना चाहिए। न्यायाधीश के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में प्रयोग किया जाना उसके विवेक के भीतर एक मामला है। "

इस न्यायालय की संविधान पीठ ने यह निर्धारित किया है कि जहां पक्षकारों के बीच समझौता ब्याज देने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है और जहां पक्षकार ब्याज का दावा करता है और वह विवाद मध्यस्थ को भेजा जाता है, वहां उसके पास बकाया ब्याज देने की शक्ति होगी। घोषित कानून को संभावित रूप से लागू माना गया है।

9. एन. सी. बुधराज (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय की एक अन्य संविधान पीठ ने मध्यस्थ द्वारा पूर्व-संदर्भ अवधि के लिए ब्याज देने के प्रश्न पर विचार किया। उस संबंध में, चर्चा की गई है और यह तब तक देखा गया है जब तक कि मध्यस्थता समझौते में अनुबंध के तहत देय राशि पर ब्याज के दावे के लिए मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र को बाहर करने के लिए कुछ भी नहीं है या देय राशि पर ब्याज का दावा करने का कोई प्रावधान नहीं है, मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की खंड 29 के तहत पूर्व-संदर्भ

अवधि के लिए ब्याज देने के लिए मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र को बरकरार रखना होगा। बहुमत की राय में, इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया हैः

> "25. यदि यह स्थिति है, तो जो अदालतें वादियों को विवादों के समाधान के वैकल्पिक तरीके का विकल्प चुनने और उनका लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, वे उन लोगों को दंडित या गंभीर नुकसान में डालेंगी जो इसका लाभ उठाते हैं। तर्क और तर्क दोनों को अदालतों को मध्यस्थ के पक्ष में अधिक झुकाव रखने के लिए परामर्श देना चाहिए जो पक्षों के बीच पूर्ण और पूर्ण न्यायाधीश करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियों को उसी तरह से धारण करता है जिस तरह से दीवानी अदालत उसी विवाद को जब्त कर सकती थी। पक्षकारों के बीच अनुबंध से उत्पन्न या उससे संबंधित सभी विवादों और दावों को मध्यस्थता द्वारा से निपटाने के लिए सहमत होने से संबंधित पक्षकार को अपने अधिकारों को सही साबित करने के लिए दीवानी अदालत का सहारा लेने के बजाय किसी भी दावे को छोड़ दिया गया माना नहीं जा सकता है जो अन्यथा वह अदालतों के समक्ष सफलतापूर्वक दावा कर सकता था और राहत प्राप्त कर सकता था। मध्यस्थता द्वारा से विवादों के निपटारे के लिए सहमत होने से, संबंधित पक्ष को यह समझना चाहिए कि उसने केवल कम बोझिल प्रक्रिया, देरी और खर्च के साथ निर्णय के एक अलग मंच का विकल्प चुना है और विभिन्न कानूनों के तहत अपने सभी या किसी भी मूल अधिकार को नहीं परित्याग करनाा है, जिसके अनुसार केवल मध्यस्थ भी उसे संदर्भित दावों पर निर्णय लेने के लिए बाध्य है। जब तक मध्यस्थता समझौते में अनुबंध के तहत देय राशि पर ब्याज के दावे को स्वीकार करने के

लिए मध्यस्थ की अधिकार क्षेत्र को बाहर करने के लिए कुछ भी नहीं है, या देय राशि पर ब्याज का दावा करने और अनुबंध के तहत देय होने के लिए कोई निषेध नहीं है, मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की खंड 29 के अधीन सभी अवधियों के संबंध में ब्याज पर विचार करने और अधिनिर्णय करने के लिए मध्यस्थ की अधिकार क्षेत्र और वह भी उसके तहत अदालत की शक्तियों को बरकरार रखना होगा। यह निवेदन कि मध्यस्थ को अपनी नियुक्ति की तारीख से पहले की अवधि के लिए ब्याज देने या संदर्भ में प्रवेश करने का अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकता है, जो केवल उसे ही शक्ति प्रदान करता है, हमारे हाथों में स्वीकार करने के लिए बहुत बासी और तकनीकी है, इस सरल कारण से कि हर मामले में एक मध्यस्थ की नियुक्ति या अधिकारों को सही साबित करने के लिए अदालत का सहारा लेना केवल पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न होने और अनसुलझे रहने के बाद ही हो सकता है, और यदि मध्यस्थ के पास एक समय पर और मध्यस्थ की नियुक्ति से पहले की अवधि के लिए उत्पन्न विवादों से निपटने और निर्णय लेने की शक्ति है, तो यह समझ से परे है कि मध्यस्थ को क्यों और किस कारण से और किस औचित्य के साथ अस्वीकार किया जाना चाहिए।

26. ऊपर बताए गए सभी कारणों के लिए, हम यह अभिनिर्धारित करते हुए संदर्भ का उत्तर देते हैं कि न्यायालय के हस्तक्षेप के साथ या उसके बिना नियुक्त मध्यस्थ को पूर्व-संदर्भ अवधि के लिए देय और देय राशि पर ब्याज देने का अधिकार क्षेत्र है, ऐसे किसी भी ब्याज का दावा करने या देने के लिए अनुबंध में कोई विशिष्ट शर्त या

निषेध की अनुपस्थिति में में। जेना मामले में एक उल्लंघन करने का निर्णय सही स्थिति निर्धारित नहीं करता है और संभावित रूप से खारिज कर दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि यह निर्णय किसी भी पक्ष को हकदार नहीं बनाएगा और न ही यह किसी भी अदालत को उन कार्यवाही को फिर से खोलने का अधिकार देगा जो पहले से ही अंतिम हो चुकी हैं, और केवल किसी भी लंबित कार्यवाही पर लागू होती हैं। कोई लागत नहीं।"

यह भी देखा गया है कि जी. सी. रॉय के मामले (सुप्रा) को कार्यकारी अभियंता (सिंचाई) बालीमेला के मामले (सुप्रा) को खारिज करने के लिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह पूर्व-संदर्भ अवधि के लिए ब्याज देने के लिए मध्यस्थ की शक्ति से संबंधित है।

10. हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में इस न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ बनाम.जम्मू और कश्मीर राज्य (1992) 4 एस. सी. सी. 217 ने निर्धारित किया है कि मध्यस्थ के पास सिविल प्रक्रिया संहिता की खंड 34 के सिद्धांत के आधार पर मुकदमेबाजी का इंतजार देने की शक्ति है, हालांकि यह लागू नहीं है। हालाँकि, इस अवलोकन पर विचार किया जाना चाहिए यदि मुकदमेबाजी का इंतजार ब्याज देने के लिए समझौते में कोई स्पष्ट बाधा नहीं है क्योंकि यह केवल जी. सी. रॉय (सुप्रा) में निर्धारित का पालन करता है। इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्धारित किया हैः

"5. ब्याज के सवाल का आसानी से निपटारा किया जा सकता है क्योंकि यह इस न्यायालय के हाल के फैसलों में शामिल है। सचिव, सिंचाई विभाग, उड़ीसा सरकार अन्य अन्य मामले में इस न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की पीठ के नवीनतम निर्णय का उल्लेख करना

पर्याप्त है। जी. सी. रॉय यद्यपि उक्त निर्णय मुकदमेबाजी का इंतजार देने के लिए मध्यस्थ की शक्ति से संबंधित है, निर्णय का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि मध्यस्थ निर्णय की तारीख से लेकर डिक्री की तारीख या प्राप्ति की तारीख, जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए ब्याज देने में सक्षम है। यह भी काफी तार्किक है, जबकि एक मध्यस्थ के संदर्भ में प्रवेश करने से पहले की अवधि के लिए ब्याज का अवार्ड मूल कानून का विषय है, अवार्ड के बाद की अवधि के लिए ब्याज का अनुदान प्रक्रिया का विषय है। सिविल प्रक्रिया संहिता की खंड 34 में अल्पावधि के साथ-साथ डिक्री के बाद की अवधि के लिए ब्याज देने का प्रावधान है और खंड 34 का मुकदमेबाजी का इंतजार के समक्ष कार्यवाही के लिए लागू माना गया है, हालांकि इस तरह की खंड लागू नहीं हो सकती है। इस संबंध में, भारत संघ बनाम बंगो स्टील फर्नीचर (प्रा.) लिमिटेड ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1032 के निर्णय को गुजरात जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम यूनिक इरेक्टर्स (गुजरात) पी. लिमिटेड 1989 1,532 एस. सी. सी. के निर्णय के रूप में भी देखा जा सकता है, जो कुछ अलग तर्क पर उक्त शक्ति को बरकरार रखता है। इसलिए हम सोचते हैं कि आइटम सं 8 पर दिए गए निर्णय को बरकरार रखा जाना चाहिए था।"

11. सईद अहमद (उपरोक्त) में इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया गया है। उड़ीसा राज्य बनाम बी. एन. अग्रवाल, (1997) 2 एस. सी. सी. 469 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्धारित किया हैः

"18. उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए अब ब्याज देने के लिए मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता है।

जिन सिद्धांतों को अब अच्छी तरह से स्थापित कहा जा सकता है, वे यह हैं कि मध्यस्थ के पास उन मामलों में पूर्व-संदर्भ ब्याज देने का अधिकार क्षेत्र है जो ब्याज अधिनियम, 1978 लागू होने के बाद उत्पन्न हुए थे। ब्याज अधिनियम, 1978 के लागू होने से पहले की अवधि से संबंधित उन मामलों के संबंध में, किसी भी ठोस कानून, अनुबंध या उपयोग की अनुपस्थिति में में, मध्यस्थ के पास ब्याज देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। जिस अवधि के दौरान जी. सी. रॉय मामले और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन लिमिटेड मामले में निर्णय को देखते हुए मध्यस्थता की कार्यवाही लंबित थी, मध्यस्थ के पास ब्याज देने की शक्ति है। अवार्ड के बाद की अवधि के लिए ब्याज देने की मध्यस्थ की शक्ति भी मौजूद है और इस निर्णय के बाद के भाग में 1994 की दीवानी याचिका सं 9234 से संबंधित चर्चा में इस पहलू पर विचार किया गया है।"

12. बी. एन. अग्रवाल (ऊपर) के निर्णय पर इस न्यायालय द्वारा सईद अहमद (ऊपर) के मामले में इस प्रकार विचार किया गया है और अलग किया गया हैः

"20. इसके बाद अपीलकर्ता ने उड़ीसा राज्य बनाम बी. एन. अग्रवाल (1997) 2 एस. सी. सी. 469 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। उस मामले में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मध्यस्थ के पास निर्णय देने का अधिकार क्षेत्र हैः(i) पूर्व-संदर्भ अवधि के लिए ब्याज, (ii) मुकदमेबाजी का इंतजार के लिए ब्याज, और (iii) भविष्य का ब्याज। इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि "दरों, सामग्रियों और कारीगरी" से संबंधित अनुबंध के खंड (4) का

निम्नलिखित भाग ठेकेदार के दावों पर मध्यस्थ द्वारा ब्याज के अवार्ड पर रोक नहीं लगाता हैः(एस. सी. सी. पी. 478, पैरा 22)

समझौते की मद के तहत रोकी गई राशि पर कोई ब्याज देय नहीं है।

उक्त खंड की व्याख्या करते हुए (जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि रोकी गई राशि पर ब्याज देय नहीं था), इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह केवल नियोक्ता राज्य द्वारा दोष देयता अवधि के लिए प्रतिधारण धन के लिए रोकी गई राशि का उल्लेख करता है। इस न्यायालय ने वास्तव में इस स्थिति को स्पष्ट किया कि यदि अनुबंध की शर्तों में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि कोई ब्याज देय नहीं होगा, तो मध्यस्थ को ब्याज देने का अधिकार क्षेत्र नहीं मिलेगा। चूंकि वर्तमान मामले में खंड जी. 09 में एक स्पष्ट बार है और यह बी. एन. अग्रवाल (सुप्रा) में विचार किए गए खंड से अलग है, इसलिए उक्त निर्णय से भी कोई सहायता नहीं मिलती है।"

बी. एन. अग्रवाल (सुप्रा) में इस न्यायालय ने कहा है कि "दरों, सामग्रियों और कारीगरी" से संबंधित अनुबंध के खंड 4 ने ठेकेदार के दावों पर मध्यस्थ द्वारा ब्याज देने पर रोक नहीं लगाई है। शर्त यह थी कि समझौते के तहत रोकी गई राशि पर कोई ब्याज देय नहीं था।

13. सईद अहमद (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने यू. पी. राज्य बनाम यू. पी. में निर्णय भेजा है। हरीश चंद्र एंड कंपनी (1999) 1 एस. सी. सी. 63, जिसमें इस न्यायालय ने समझौते के खंड 1.9 में निहित शर्त की व्याख्या की है जो इस न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचार के लिए आई थी। खंड 1 का सार नीचे दिया गया हैः

"1.9 विवाद आदि के कारण भुगतान में देरी के लिए कोई दावा नहीं- ब्याज या हर्जाने के लिए सरकार द्वारा किसी भी धन या शेष राशि के संबंध में कोई दावा नहीं किया जाएगा जो किसी भी विवाद, अंतर या आवधिक या अंतिम भुगतान को चिह्नित करने में प्रभारी अभियंता के बीच गलतफहमी या किसी अन्य मामले में सरकार के पास हो सकता है।"

इस न्यायालय ने खंड 1.9 की व्याख्या की है और कहा है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसे प्रतिवादी-ठेकेदार के खिलाफ निकाला जा सके कि वह निर्णय के लिए रखी गई प्रासंगिक वस्तुओं पर मध्यस्थ के समक्ष हर्जाने के रूप में ब्याज का दावा नहीं कर सकता है।

सईद अहमद (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय ने हरीश चंद्र (सुप्रा) मामले में भी निर्णय को अलग किया है जिसमें खंड 1.09 इस प्रकार विचार के लिए आया थाः

"17. x x x x इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उक्त खंड नुकसान के किसी भी दावे या किए गए कार्य के भुगतान के दावे पर ब्याज के अधिनिर्णय पर रोक नहीं लगाता है। हम इस तरह के निर्णय के लिए तर्क नीचे निकालते हैंः(एस. सी. सी. पी. 67, पैरा 10)

"10. खंड पर केवल एक नज़र डालने से पता चलता है कि हर्जाने के रूप में ब्याज के दावे पर सरकार के खिलाफ केवल एक निर्दिष्ट प्रकार की राशि के संबंध में विचार नहीं किया जाना था, अर्थात्, कोई भी धन या शेष राशि जो किसी भी विवाद, प्रभारी अभियंता और ठेकेदार के बीच अंतर, या आवधिक या अंतिम भुगतान करने में प्रभारी अभियंता और ठेकेदार के बीच गलतफहमी या किसी अन्य मामले में

सरकार के पास हो सकती है। 'या किसी अन्य मामले में जो कुछ भी हो' शब्द उन धन या शेष राशि से संबंधित विवाद को भी संदर्भित करते हैं जो समझौते के अनुसार सरकार के पास पड़े हो सकते हैं जिसका अर्थ है कि प्रतिभूति जमा या प्रतिधारण राशि या कोई अन्य राशि जो सरकार के पास हो सकती है और जिसका धनवापसी सरकार द्वारा रोक दी गई हो। हर्जाने के दावे या किए गए काम के लिए भुगतान के दावे और जिसके लिए भुगतान नहीं किया गया था, स्पष्ट रूप से किसी भी धन को शामिल नहीं करेगा जिसे सरकार के पास पड़ा हुआ कहा जा सकता है। नतीजतन, इस खंड की स्पष्ट भाषा में, ऐसा कोई निषेध नहीं है जिसे प्रतिवादी ठेकेदार के खिलाफ माना जा सके कि वह निर्णय के लिए रखी गई प्रासंगिक वस्तुओं पर मध्यस्थ के समक्ष नुकसान के रूप में ब्याज का दावा नहीं कर सकता है। "

(जोर दिया गया)

18. हरीश चंद्र (1999) 1 एस. सी. सी. 63 में खंड 1 के एक अलग संस्करण पर विचार किया गया था। उस खंड के प्रतिबंधात्मक शब्दों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वह नुकसान के दावे या किए गए और भुगतान नहीं किए गए कार्य के भुगतान के दावे पर ब्याज के अधिनिर्णय पर रोक नहीं लगाता है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उक्त खंड केवल उन राशियों पर ब्याज देने पर रोक लगाता है जो प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि या किसी अन्य राशि के रूप में सरकार के पास पड़ी हो सकती हैं, जिसकी वापसी सरकार द्वारा रोक दी गई थी।

19. लेकिन वर्तमान मामले में, खंड जी. 1.09 काफी अलग है। इसमें विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया है कि प्रभारी अभियंता और ठेकेदार के बीच किसी भी विवाद, मतभेद या गलतफहमी के कारण या आवधिक या अंतिम भुगतान करने में प्रभारी अभियंता की ओर से किसी भी देरी के संबंध में या किसी भी अन्य संबंध में देय किसी भी धन के संबंध में कोई ब्याज देय नहीं होगा। इस मामले में खंड जी.1.09 के तहत प्रतिबंध आत्यन्तिक होने के कारण, हरीश चंद्र (सुप्रा) में निर्णय किसी भी तरह से अपीलकर्ता की सहायता नहीं करेगा।"

हरीश चंद्र (सुप्रा) मामले में, इस न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि खंड 1.09 किए गए कार्य के भुगतान के लिए हर्जाने के दावे के लिए ब्याज के अधिनिर्णय पर रोक नहीं लगाता है और जिसके लिए भुगतान नहीं किया गया था, वह स्पष्ट रूप से किसी भी धन को शामिल नहीं करेगा जिसे सरकार के पास पड़ा हुआ कहा जा सकता है।

14. हमारी राय में, यह प्रत्येक मामले में निष्कासन खंड की प्रकृति पर निर्भर करेगा। यदि कोई स्पष्ट शर्त है जो मुकदमेबाजी का इंतजार पर रोक लगाती है, तो जाहिर है, यह मध्यस्थ द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता है। मुकदमेबाजी का इंतजार का अधिनिर्णय अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ समझौते के समग्र इरादे पर निर्भर होना चाहिए और जिसे स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है।

15. सईद अहमद (सुप्रा) मामले में, इस न्यायालय ने अधीक्षण अभियंता बनाम बी. सुब्बा रेड्डी (1999) 4 एस. सी. सी. 423 में निर्णय भेजा है और इस प्रकार टिप्पणी की हैः

"11. मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों से संबंधित दो और निर्णयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अधीक्षण अभियंता बनाम बी. सुब्बा रेड्डी (1999) 4 एस. सी. सी. 423 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पूर्व-संदर्भ अवधि के लिए ब्याज केवल तभी दिया जा सकता है जब उस आशय का कोई समझौता हो या यदि यह ब्याज अधिनियम, 1978 के तहत अनुज्ञेय हो। इसलिए, पूर्व-संदर्भ अवधि के लिए ब्याज के दावे की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो समझौते के अनुसार या ब्याज अधिनियम, 1978 के तहत वर्जित है। हालाँकि, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि मध्यस्थ मुकदमेबाजी का इंतजार और भविष्य का ब्याज प्रदान कर सकता है।"

सईद अहमद (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय ने राजस्थान राज्य और अन्र बनाम अन्र में भी निर्णय भेजा है। फेरो कंक्रीट कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड (2009) 12 एससीसी 1 इस प्रकारः

"12. ब्याज से संबंधित सिद्धांतों को इस न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य बनाम फेरो कंक्रीट कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड (2009) 12 एस. सी. सी. 1 में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया थाः

(क) जहाँ किसी ऋण या क्षति पर ब्याज का प्रावधान किया जाता है, वहाँ किसी भी समझौते में ऐसे समझौते के अनुसार ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

(ख) जहां किसी ऋण या क्षति पर ब्याज का भुगतान अनुबंध में स्पष्ट प्रावधान द्वारा वर्जित है, वहां कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

(ग) जहां अनुबंध में कोई स्पष्ट बाधा नहीं है और जहां ब्याज के भुगतान का भी कोई प्रावधान नहीं है, वहां ब्याज अधिनियम की खंड 3 के सिद्धांत लागू होंगे और इसके परिणामस्वरूप ब्याज देय होगाः

(i) जहां कार्यवाहियां किसी निश्चित समय पर लिखित लिखत के आधार पर देय ऋण (निर्धारित राशि) से संबंधित हैं, तो उस तारीख से जब ऋण देय है, कार्यवाही शुरू होने दायर करने की तारीख तक;

(ii) जहां कार्यवाही नुकसान की वसूली या किसी ऐसे ऋण की वसूली के लिए है जो एक निश्चित समय पर देय नहीं है, तो उस व्यक्ति द्वारा दिए गए लिखित नोटिस में उल्लिखित तिथि से जो दावे के लिए उत्तरदायी व्यक्ति पर दावा करता है कि ब्याज का दावा किया जाएगा।

(घ) मुकदमेबाजी का इंतजार और भावी ब्याज का भुगतान ब्याज अधिनियम, 1978 के प्रावधानों द्वारा नहीं, बल्कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की खंड 34 के प्रावधानों या मामले के अनुसार मध्यस्थता को नियंत्रित करने वाले कानून के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।"

सईद अहमद (उपरोक्त) में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान लागू थे।

16. भारत संघ बनाम ब्राइट पावर प्रोजेक्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड मामले में इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ। (2015) 9 एस. सी. सी. 695 ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की खंड 31 (7) (ए) में निहित प्रावधानों पर विचार किया है और उक्त खंड में "जब तक कि पक्षों द्वारा अन्यथा सहमति न हो" शब्दों पर विचार किया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां तक निष्पादन की तारीख से

अवार्ड की तारीख तक ब्याज के अवार्ड का संबंध है, मध्यस्थ अनुबंध की शर्तों से बाध्य है। इस न्यायालय ने अनुबंध के खंड 13 (3) पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि एक बार इस बात पर सहमत होने के बाद कि ठेकेदार अनुबंध के तहत भुगतान की जाने वाली राशि पर किसी भी ब्याज का दावा नहीं करेगा, वह ब्याज का दावा नहीं कर सकता था। मध्यस्थ ब्याज देते समय समझौते की शर्तों की खंड 31 (7) (ए) के प्रावधानों और खंड 13 (3) की बाध्यकारी प्रकृति पर विचार करने में विफल रहा। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की खंड 31 (7) (ए) के संबंध में इस न्यायालय ने भारत संघ बनाम उज्ज्वल विद्युत परियोजनाएं (उपर्युक्त) मामले में इस प्रकार टिप्पणी की हैः

> "18. अधिनियम की खंड 31 (7) (ए) को ब्याज देने के संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पहले मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पढ़ा और व्याख्या की जानी चाहिए थी। उक्त खंड, जिसे यहाँ ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, पक्षों के बीच हुए समझौते को अधिक सम्मान देता है। यदि समझौते के पक्ष एक-दूसरे को ब्याज का भुगतान नहीं करने के लिए सहमत होते हैं, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण को मुकदमेबाजी का इंतजार देने का कोई अधिकार नहीं है"

1996 के अधिनियम की खंड 31 (7) (ए) मध्यस्थ को "जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो", मुकदमेबाजी का इंतजार का अधिकार प्रदान करती है। इस प्रकार, खंड 31 (7) (ए) में निहित प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि पक्षों के बीच अनुबंध को महत्व दिया गया है और यह मध्यस्थ के लिए बाध्यकारी है। मध्यस्थ की शक्ति का निर्णय करते समय मध्यस्थता खंड पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है और यदि ब्याज देने पर अनुबंध में कोई प्रतिबंध निहित है, तो यह किन मदों पर काम करता है और मध्यस्थता खंड में मध्यस्थ को क्या शक्तियां प्रदान की गई हैं और क्या

ब्याज देने पर प्रतिबंध निश्चित अवधि तक सीमित किया गया है या यह मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही विचाराधीनता रहने से संबंधित है।

17. श्री कामची अम्मान कंस्ट्रक्शंस (उपरोक्त) में, यह देखा गया कि 1996 के नए अधिनियम की खंड 31 में "जब तक कि पक्षों द्वारा अन्यथा सहमति न हो" शब्द स्पष्ट करते हैं कि मुकदमेबाजी का इंतजार के अवार्ड के लिए अनुबंध की शर्तों से बाध्य है। यह भी इस प्रकार आयोजित किया गया थाः

> "19. नए अधिनियम की खंड 31 (7) "जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो" शब्दों का उपयोग करके स्पष्ट करती है कि मध्यस्थ वाद हेतुक कारण की तारीख से अवार्ड की तारीख तक ब्याज के अवार्ड के रूप में अनुबंध की शर्तों से बाध्य है। इसलिए, जहां पक्षकार इस बात पर सहमत हुए थे कि कोई ब्याज देय नहीं होगा, मध्यस्थ न्यायाधिकरण वाद हेतुक उत्पन्न होने की तारीख से अधिनिर्णय की तारीख के बीच ब्याज नहीं दे सकता है।
>
> 20. हमारा विचार है कि इंजीनियर्स-डी-स्पेस-एज (ऊपर) और मदनानी (ऊपर) में निर्णय एक अन्य कारण से लागू नहीं होते हैं। इंजीनियर्स-डी-स्पेस-एज (सुप्रा) और मदनानी (सुप्रा) में मध्यस्थ ने विचाराधीन अवधि के मुकदमेबाजी का इंतजार दिया था। इस न्यायालय ने पुराने अधिनियम के तहत ऐसे ब्याज के अधिनिर्णय को इस आधार पर बरकरार रखा कि मध्यस्थ को यह तय करने का विवेकाधिकार था मुकदमेबाजी का इंतजार अवधि के दौरान ब्याज दिया जाना चाहिए या नहीं और वह लंबित अवधि के लिए ब्याज के रूप में संविदात्मक शर्तों से बाध्य नहीं था। लेकिन तत्काल मामले में

मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने विचाराधीन अवधि के मुकदमेबाजी का इंतजार देने से इनकार कर दिया है। जहां मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अपने विवेकाधिकार का प्रयोग किया है और विचाराधीन अवधि के मुकदमेबाजी का इंतजार देने से इनकार कर दिया है, भले ही उन दोनों मामलों में सिद्धांत लागू हों, मध्यस्थ के फैसले में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर भी इंजीनियर्स-डी-स्पेस-एज (ऊपर) और मदनानी (ऊपर) में निर्णय लागू नहीं होते हैं। जो भी हो सकता है"

18. यह न्यायालय भारत संघ बनाम क्राफ्टर्स इंजीनियरिंग एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड में है। (2011) 7 एस. सी. सी. 279 ने अभिनिर्धारित किया है कि समझौते में एक प्रावधान द्वारा, ब्याज देने के लिए मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र को बाहर रखा जा सकता है। इस न्यायालय ने संबंधित खंड में निहित प्रावधान की तुलना में दावे की प्रकृति पर विचार किया।

19. ऊपर उल्लिखित विभिन्न निर्णयों से यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय की जी. सी. रॉय (उपरोक्त) संविधान पीठ ने निर्धारित किया है जहां समझौते में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि देय राशि पर कोई भी मुकदमेबाजी का इंतजार देय नहीं होगा। मध्यस्थ के पास ब्याज देने की कोई शक्ति नहीं है। एन. सी. बुधराज (ऊपर) में एक संविधान पीठ ने कहा है कि यदि मध्यस्थता समझौते में ब्याज के दावे पर विचार करने के लिए मध्यस्थ की अधिकार क्षेत्र को बाहर करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो सभी अवधियों के संबंध में विचार करने और ब्याज देने के लिए मध्यस्थ की अधिकार क्षेत्र अधिनियम की खंड 29 के अधीन है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी में। लिमिटेड (सुप्रा) इस न्यायालय ने जी. सी. रॉय (सुप्रा) में निर्णय का पालन किया है और यह निर्धारित किया है कि खंड 34 के सिद्धांतों के आधार पर मध्यस्थ को मुकदमेबाजी का

इंतजार भी देने की शक्ति होगी। बी. एन. अग्रवाल (सुप्रा) में, इस न्यायालय ने फिर से जी. सी. रॉय (सुप्रा) और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का अनुसरण किया है। लिमिटेड (सुप्रा) मुकदमेबाजी का इंतजार ब्याज देने की मध्यस्थ की शक्ति के संबंध में और यह अभिनिर्धारित किया गया कि मध्यस्थ को ब्याज देने की शक्ति है। हरीश चंद्र (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय ने खंड 1.9 की व्याख्या की जिसमें प्रावधान किया गया था कि सरकार के पास पड़े किसी भी धन या शेष राशि के संबंध में ब्याज या हर्जाने के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसे ठेकेदार के खिलाफ निर्णय के लिए रखी गई प्रासंगिक वस्तुओं पर मध्यस्थ के समक्ष हर्जाने के रूप में ब्याज का दावा नहीं करने के लिए समाप्त किया जा सके। फेरो कंक्रीट कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड (सुप्रा) में इस न्यायालय ने खंड 4 पर विचार किया जिसमें एक शर्त थी कि समझौते के तहत रोकी गई राशि पर कोई ब्याज देय नहीं था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि दर, सामग्री और कारीगरी से संबंधित खंड 4 उक्त मामले में ठेकेदार के दावों पर मध्यस्थ द्वारा ब्याज के अधिनिर्णय पर रोक नहीं लगाता है। सईद अहमद (सुप्रा) में इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि ब्याज का अधिनिर्णय समझौते के खंड की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ब्राइट पावर प्रोजेक्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) में इस न्यायालय ने 1996 के अधिनियम की खंड 31 (7) (ए) में नियोजित "जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो" अभिव्यक्ति पर विचार किया है और यह निर्धारित किया है कि अनुबंध पर रोक लगाने वाले मामलों में ठेकेदार ब्याज का दावा नहीं कर सकता था। 1996 के अधिनियम की खंड 31 (7) (ए) का प्रावधान मध्यस्थ के लिए बाध्यकारी है। श्री कामची अम्मान कंस्ट्रक्शंस (ऊपर) में भी ऐसा ही दृष्टिकोण लिया गया है।

20. अब हम इंजीनियर-डी-स्पेस-एज (उपरोक्त) में दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए इस न्यायालय के निर्णय की शुद्धता के प्रश्न पर आते हैं जिसे हमारे विचार के

लिए भेजा गया है जिसमें इस न्यायालय ने जी. सी. रॉय के मामले पर विचार करने के बाद इस प्रकार टिप्पणी की हैः

> "3..संविधान पीठ ने कानूनी स्थिति के रूप में जो कहा है, उससे यह प्रतीत होगा कि आम तौर पर एक व्यक्ति जो अपने धन से वंचित है, जिसके लिए वह वैध रूप से अधिकार का हकदार है, वह उससे वंचित होने पर क्षतिपूर्ति का हकदार है, इसे किसी भी नाम से कहें। यह सिविल प्रक्रिया संहिता की खंड 34 में निर्धारित सिद्धांत के संदर्भ में होगा। उनके अधिपतियों ने बताया कि मध्यस्थ के मामले में अन्यथा रखने का कोई कारण या सिद्धांत नहीं था। यह इंगित करते हुए कि मध्यस्थ पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए एक वैकल्पिक मंच है, इसने कहा कि उसके पास पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी विवादों और मतभेदों को तय करने की शक्ति होनी चाहिए और यदि उसे मुकदमेबाजी का इंतजार देने की शक्ति से वंचित किया जाना है, तो उसके हकदार पक्ष को अदालत में जाने की आवश्यकता होगी, जिसके परिणामस्वरूप कई कार्यवाहियां होंगी, एक ऐसी स्थिति जिससे अदालत को बचने का प्रयास करना चाहिए। हालाँकि, मुकदमेबाजी का इंतजार (iii) में अवलोकन पर रखा गया था जिसमें यह बताया गया है कि एक मध्यस्थ एक समझौते का एक प्राणी है और यदि पक्षों के बीच समझौता ब्याज के भुगतान को प्रतिबंधित करता है तो मध्यस्थ को उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, उनके प्रभुत्वों के अनुसार मध्यस्थ से अपेक्षा की जाती है कि वह देश के सामान्य कानून के अनुसार कार्य करेगा और अपना अवार्ड देगा, लेकिन एक समझौते के अधीन, बशर्ते कि

समझौता वैध और कानूनी हो। अंत में, यह बताया गया कि मुकदमेबाजी का इंतजार मूल कानून का विषय नहीं है, जैसे कि संदर्भ से पहले की अवधि के लिए ब्याज। उनके अधिपतियों ने निष्कर्ष निकाला कि जहां पक्षों के बीच समझौता ब्याज देने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है और जहां कोई पक्ष ब्याज का दावा करता है और उस विवाद को मध्यस्थ को भेजा जाता है, तो उसके पास इस सरल कारण से मुकदमेबाजी का इंतजार देने की शक्ति होगी कि ऐसे मामले में यह माना जाता है कि ब्याज पक्षों के बीच समझौते का एक निहित शब्द था; यह तब मध्यस्थ द्वारा विवेक का प्रयोग करने का विषय है। इसलिए संविधान पीठ के उपरोक्त निर्णय में कानून की स्थिति स्पष्ट रूप से बताई गई है।

4. हम संदर्भ से पहले की अवधि के लिए ब्याज देने के संबंध में किसी मामले पर विचार नहीं कर रहे हैं। हम मध्यस्थ द्वारा ब्याज के अवार्ड के संबंध में एक मामले पर विचार कर रहे हैं। इसलिए, संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या पहले निकाले गए अनुबंध के खंड 13 के उपखंड (जी) को देखते हुए मध्यस्थ को अनुबंध के तहत ब्याज देने से प्रतिबंधित किया गया था। अब उपखंड (छ) में शब्द केवल आयुक्त को ब्याज के लिए किसी भी दावे पर विचार करने से रोकता है और मध्यस्थ को ब्याज देने से नहीं रोकता है। प्रारंभिक शब्द "ब्याज के लिए कोई दावा आयुक्त द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा" स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि इरादा आयुक्त को ठेकेदार को भुगतान में देरी के कारण ब्याज देने से प्रतिबंधित करना था। खंड का कड़ाई से इस सरल कारण से अर्थ लगाया जाना चाहिए कि जैसा कि संविधान पीठ

ने इंगित किया है, आम तौर पर, एक व्यक्ति जिसके पास वैध दावा है, वह उचित समय के भीतर भुगतान करने का हकदार है और यदि भुगतान में उचित समय से अधिक देरी हुई है, तो वह वैध रूप से उस देरी के लिए क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है, जो भी नाम उस ओर से उसके दावे को दिया जाए।"

21. सईद अहमद (ऊपर) में इंजीनियर्स-डी-स्पेस-एज (सुप्रा) में निर्णय पर विचार किया गया है और यह देखा गया है कि इसका उपयोग एक विचित्र तर्क का समर्थन करने के लिए नहीं किया जा सकता है कि सरकार या विभाग पर ब्याज का भुगतान करने पर प्रतिबंध मध्यस्थ द्वारा ब्याज देने पर प्रतिबंध नहीं है। इस न्यायालय ने इंजीनियर्स-डी-स्पेस-एज (सुप्रा) में की गई कुछ टिप्पणियों की शुद्धता के बारे में इस हद तक संदेह व्यक्त किया कि मध्यस्थ अनुबंध में एक्सप्रेस बार की अनदेखी करते हुए मुकदमेबाजी का इंतजार का फैसला दे सकता है। लेकिन इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर आगे विचार नहीं किया क्योंकि सईद अहमद (सुप्रा) में मामला 1996 के मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत उत्पन्न हुआ था, और मध्यस्थ द्वारा ब्याज देने के संबंध में नए अधिनियम के तहत एक विशिष्ट प्रावधान था। सईद अहमद (सुप्रा) में की गई चर्चा से यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि यह खंड और दावे आदि की प्रकृति पर निर्भर करेगा और यह इस शर्त पर विचार करने पर पाया जाना आवश्यक है कि क्या ब्याज वर्जित है, यदि हां, तो अनुबंध के तहत किस राशि पर ब्याज वर्जित है।

22. टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एक अन्य बनाम जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, (2012) 12 एस. सी. सी. 10 में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने उस प्रश्न पर विचार किया है जिसे तत्काल मामले में संदर्भित किया गया है और इसे खंड 1.2.14 और 1.2.15 के संदर्भ में निर्धारित किया गया है,

जिसमें भुगतान न करने या प्रतिभूति जमा में किए गए या पड़े काम के लिए देय राशि के विलंबित भुगतान की किसी भी स्थिति में मनोरंजन या ब्याज के भुगतान पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रकार, मध्यस्थ के पास मुकदमेबाजी का इंतजार ब्याज देने की कोई शक्ति नहीं थी। इस न्यायालय ने इंजीनियर्स-डी-स्पेस एज (सुप्रा) और मदनानी कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (पी) लिमिटेड (ऊपर) में निर्णयों की शुद्धता पर भी संदेह किया है। इस अदालत ने टिहरी पनबिजली विकास निगम (सुप्रा) में उपरोक्त खंडों और विभिन्न फैसलों पर विचार किया है जिसमें हममें से एक न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अदालत की ओर से बात की थी। इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्धारित किया है:-

> "14. यह न्यायालय को इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित करेगा कि वर्तमान मामले में पक्षों के बीच विवाद का प्रमुख कारण क्या है, अर्थात् ब्याज के भुगतान के संबंध में मुद्दा। खंड 1.2.14 और 1.2.15 जिन पर दोनों पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहुत सारे तर्क दिए गए हैं, उन्हें अब नीचे निकाला जा सकता है:
>
> भाग-II
>
> अनुबंध की शर्तें
>
> 1.2.14 विवाद आदि के कारण विलंबित भुगतान के लिए कोई दावा नहीं-ठेकेदार इस बात से सहमत है कि पक्षकारों के बीच किसी भी विवाद, मतभेद या गलतफहमी के कारण या तत्काल या अंतिम भुगतान करने में या किसी अन्य मामले में प्रभारी अभियंता की ओर से किसी भी देरी या चूक के संबंध में सरकार के पास पड़े किसी भी धन या शेष राशि के संबंध में सरकार द्वारा नुकसान के ब्याज के लिए कोई दावा स्वीकार या देय नहीं होगा।

1.2.15.ठेकेदार को देय धन पर ब्याज- माप पर देय राशि अवशिष्ट करने के लिए प्रभारी अभियंता की ओर से कोई चूक अनुबंध को दूषित या अमान्य नहीं करेगी, न ही ठेकेदार किसी भी गारंटी या बकाया भुगतान पर ब्याज का हकदार होगा और न ही किसी भी शेष राशि पर जो उसके खातों के अंतिम निपटान पर उसे देय हो।

पक्षों के बीच अनुबंध समझौते के उपरोक्त दो खंडों को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि दोनों खंडों द्वारा विचार की गई परिस्थितियों के कुछ अतिव्यापी होने के बावजूद, ठेकेदार को किए गए कार्यों के लिए या गारंटी के रूप में जमा में पड़ी किसी भी राशि पर, अंतरिम या अंतिम, भुगतान में देरी के लिए कोई ब्याज देय नहीं है। उपरोक्त विचारित परिणाम ऐसी स्थिति दोनों पर लागू होगा जहां भुगतान को रोकना पक्षकारों के बीच किसी विवाद या मतभेद के कारण या अन्यथा भी हो।

15. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संदर्भित इस न्यायालय के कई निर्णयों में से सिंचाई विभाग में इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय उड़ीसा सरकार बनाम जी. सी. रॉय, (1992) 1 एस. सी. सी. 508 और ढेंकनाल लघु सिंचाई प्रभाग बनाम एन. सी. बुधराज, (2001) 2 एस. सी. सी. 721 के लिए विशिष्ट सूचना की आवश्यकता होगी। भारत संघ बनाम क्राफ्टर्स एंग के मामले में इस न्यायालय की हाल की घोषणा में उपरोक्त दो निर्णयों में निर्धारित सही अनुपात पर विस्तार से विचार किया गया है। और लीजिंग (पी) लिमिटेड, (2011) 7 एस. सी. सी. 279। क्राफ्टर्स इंजीनियर्स के मामले (सुप्रा) में जी. सी. रॉय के मामले (सुप्रा) में निर्णय के अनुपात की पहचान इस अर्थ

में की गई थी कि यदि पक्षों के बीच समझौता ब्याज के अनुदान को प्रतिबंधित नहीं करता है और ब्याज के लिए किसी पक्ष के दावे को मध्यस्थ को भेजा जाता है, तो मध्यस्थ के पास ब्याज देने की शक्ति होगी। यह इस आधार पर है कि मौन के ऐसे मामले में (जहां समझौता मौन है) यह माना जाना चाहिए कि ब्याज समझौते का एक निहित शब्द था और इसलिए, क्या ऐसा दावा मान्य है, मध्यस्थ द्वारा उसे दिए गए संदर्भ में जांच की जा सकती है। उपरोक्त दृष्टिकोण, विशेष रूप से, मुकदमेबाजी का इंतजार के संबंध में है। एन. सी. बुधराज के मामले (सुप्रा) में संविधान पीठ के बाद के फैसले में पूर्व-संदर्भ अवधि के लिए ब्याज के संबंध में इसी तरह का विचार लिया गया है।

16. क्राफ्टर्स इंजीनियर्स के मामले (सुप्रा) में, पोर्ट ऑफ कलकत्ता अन्य इंजीनियर्स-डी-स्पेस-एज (सुप्रा) और मदनानी कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड अन्य यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसलों द्वारा कुछ हद तक असंगत ध्यान दें पर भी ध्यान दिया गया था। इसके बाद, यह भी देखा गया कि इंजीनियर्स-डी-स्पेस-एज के मामले (सुप्रा) में निर्णय पर सईद अहमद एंड कंपनी बनाम यू. पी. राज्य (सुप्रा) और मदनानी कंस्ट्रक्शन केस (सुप्रा) के डिसिशन को श्री कामची अम्मान कंस्ट्रक्शंस बनाम रेलवे (2010) 8 एस. सी. सी. 767 में यू. पी. राज्य (ऊपर) और मदनानी निर्माण मामले (ऊपर) में निर्णय पर विचार किया गया था। सईद अहमद के मामले (ऊपर) (एस. सी. सी. पैरा 24) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जी. सी. रॉय के मामले (1992) 1

एस. सी. सी. 508 और एन. सी. बुधराज मामले (2001) 2 एस. सी. सी. 721 में संविधान पीठ के निर्णय के आलोक में यह संदेहपूर्ण है कि क्या इंजीनियर्स-डी-स्पेस-एज के मामले (सुप्रा) में इस आशय की टिप्पणियां कि मध्यस्थ अनुबंध में एक्सप्रेस बार की अनदेखी करते हुए मुकदमेबाजी का इंतजार दे सकता है, अच्छा कानून है। श्री कामची अम्मान कंस्ट्रक्शन के मामले (सुप्रा) में मदनानी के मामले (सुप्रा) पर विचार करते हुए इस अदालत ने कहा कि मदनानी मामले (सुप्रा) में निर्णय इंजीनियर्स-डी-स्पेस-एज के मामले (सुप्रा) में निर्णय का अनुसरण करता है।

17. उपरोक्त चर्चाओं से, यह स्पष्ट है कि जहां तक मुकदमेबाजी का इंतजार ब्याज का संबंध है, जी. सी. रॉय मामले (सुप्रा) में निर्णय के पैरा 43 और 44 में निहित टिप्पणियां लागू होंगी। यद्यपि उक्त सिद्धांत का सार पहले देखा जा चुका है, फिर भी जी. सी. रॉय के मामले (सुप्रा) में निर्णय के पैरा 44 को निर्धारित करना उचित होगा जो निम्नलिखित शब्दों में हैः

44. उपरोक्त विचार को ध्यान में रखते हुए, हम सोचते हैं कि निम्नलिखित सही सिद्धांत है जिसका इस संबंध में पालन किया जाना चाहिए। जहां पक्षों के बीच समझौता ब्याज देने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है और जहां कोई पक्ष ब्याज का दावा करता है और वह विवाद (मूल राशि के दावे के साथ या स्वतंत्र रूप से) मध्यस्थ को भेजा जाता है, तो उसके पास मुकदमेबाजी का इंतजार देने की शक्ति होगी। यह इस कारण से है कि ऐसे मामले में यह माना जाना चाहिए कि ब्याज पक्षकारों के बीच समझौते का एक निहित शब्द था और

इसलिए जब पक्षकार अपने सभी विवादों को-या विवाद को ब्याज के रूप में-मध्यस्थ को संदर्भित करते हैं, तो उसके पास ब्याज देने की शक्ति होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि हर मामले में मध्यस्थ को अनिवार्य मुकदमेबाजी का इंतजार का भुगतान करना चाहिए। न्यायाधीश के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में प्रयोग किया जाना उसके विवेक के भीतर एक मामला है।

18. मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की पहली अनुसूची में संशोधन करने वाले उत्तर प्रदेश नागरिक कानून (सुधार और संशोधन) अधिनियम के प्रावधान प्रत्यर्थी ठेकेदार को किसी भी तरह से मुकदमेबाजी का इंतजार के दावे को बनाए रखने में सहायता नहीं करते हैं, क्योंकि पहली अनुसूची का पैरा 7-ए, जैसा कि संशोधित किया गया है, केवल एक सक्षम प्रावधान है जो उस स्थिति में लागू नहीं होगा जहां किए गए काम के लिए देय राशि या प्रतिभूति के रूप में जमा में पड़ी राशि के विलंबित भुगतान पर मनोरंजन या ब्याज के भुगतान पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध है। बी. एन. अग्रवाल मामले (सुप्रा) में निर्णय, जिस पर प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुकदमेबाजी का इंतजार है, एक बार फिर, ब्याज के लिए प्रत्यर्थी के दावे की सहायता नहीं करता है क्योंकि बी. एन. अग्रवाल मामले (सुप्रा) में जी. सी. रॉय मामले (सुप्रा) में ब्याज के संबंध में संविधान पीठ के विचार लंबित नहीं हो सकते थे और वास्तव में, दूर से भी संदेह नहीं किया गया था। बी. एन. अग्रवाल मामले में पीठ का अवलोकन कि जी. सी. रॉय मामले में (सुप्रा) विभाग में निर्णय। सिंचाई बनाम अभादुता जेना

(1988) 1 एस. सी. सी. 418 को केवल पूर्व-संदर्भ अवधि के लिए ब्याज प्रदान करने के संदर्भ में खारिज नहीं किया गया था। एशियन टेकस लिमिटेड मामले (सुप्रा) में भी प्रतिवादी द्वारा दिए गए निर्णय में इंजीनियर्स-डी-स्पेस-एज मामले (सुप्रा) में इस निष्कर्ष पर पहुंचने के निर्णय पर ध्यान दें गया है कि पक्षों के बीच समझौते के खंड 11 में निहित ब्याज के भुगतान पर निषेध विभाग का अधिकार था और मध्यस्थ को दावे पर विचार करने से नहीं रोका गया था। यह पहले ही देखा जा चुका है कि इंजीनियर्स-डी-स्पेस-एज मामले (सुप्रा) में निर्धारित प्रस्तावों की शुद्धता पर इस न्यायालय के बाद के फैसलों में संदेह किया गया है, जिसका संदर्भ पहले ही दिया जा चुका है।

19. खंड 1.2.14 और 1.2.15, जो पहले से ही निकाले गए और विश्लेषण किए गए हैं, ने भुगतान न करने या किए गए काम के लिए देय राशि के विलंबित भुगतान या प्रतिभूति जमा में पड़े होने की किसी भी स्थिति में मनोरंजन या ब्याज के भुगतान पर एक स्पष्ट प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले की गई चर्चाओं के आधार पर हमारा विचार है कि रुपये के दावे पर मुकदमेबाजी का इंतजार ब्याज दिया जाए। 10,17,461-उचित नहीं है। अवार्ड के साथ-साथ नीचे दिए गए न्यायालयों के आदेशों को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। इंजीनियर्स-डी-स्पेस-एज (सुप्रा) के पैरा 4 में इस न्यायालय ने कहा है कि अनुबंध के तहत प्रतिबंध मध्यस्थ पर लागू नहीं होगा, इसे सामान्य अनुप्रयोग का अवलोकन नहीं कहा जा सकता है। हमारी राय में, यह प्रत्येक मामले में अनुबंध की शर्त पर निर्भर करेगा कि क्या मध्यस्थ की मुकदमेबाजी का इंतजार देने की शक्ति स्पष्ट रूप से छीन

ली गई है। यदि उत्तर 'हाँ' है तो मध्यस्थ के पास मुकदमेबाजी का इंतजार ब्याज देने का कोई अधिकार नहीं होगा।

23. मदनानी निर्माण निगम (सुप्रा) में निर्णय इंजीनियर्स-डी-स्पेस-एज (सुप्रा) में निर्णय के बाद लिया गया है। इसे इस हद तक कम करने की भी आवश्यकता है कि अनुबंध के तहत व्यक्त शर्त मध्यस्थ को मुकदमेबाजी का इंतजार देने से रोक सकती है। मुकदमेबाजी का इंतजार ब्याज का अनुदान कई कारकों पर निर्भर कर सकता है जैसे कि समझौते में उपयोग की गई वाक्यांश-रचना, मध्यस्थता से संबंधित शक्ति प्रदान करने वाले खंड, मध्यस्थ को संदर्भित दावे और विवाद की प्रकृति और ब्याज देने की किस वस्तु की शक्ति को छीन लिया गया है और किस अवधि के लिए।

24. इस प्रकार, संदर्भ के लिए हमारा उत्तर यह है कि यदि अनुबंध स्पष्ट मुकदमेबाजी का इंतजार के अवार्ड को प्रतिबंधित करता है, तो यह मध्यस्थ द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता है। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि विलंबित भुगतान पर स्वयं ब्याज देने पर रोक को मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा मुकदमेबाजी का इंतजार देने पर त्वरित रोक के रूप में आसानी से अनुमान नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि इस न्यायालय के निर्णयों में निर्दिष्ट विभिन्न प्रासंगिक पहलुओं पर मध्यस्थ की शक्ति को हटाने पर विचार किया जाना है, यह खण्ड पीठ पर होगा कि वह गुण-दोष के आधार पर मामले पर विचार करे।

देविका गुजराल

संदर्भ उत्तर दिया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिएए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।